EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 01 January 2026

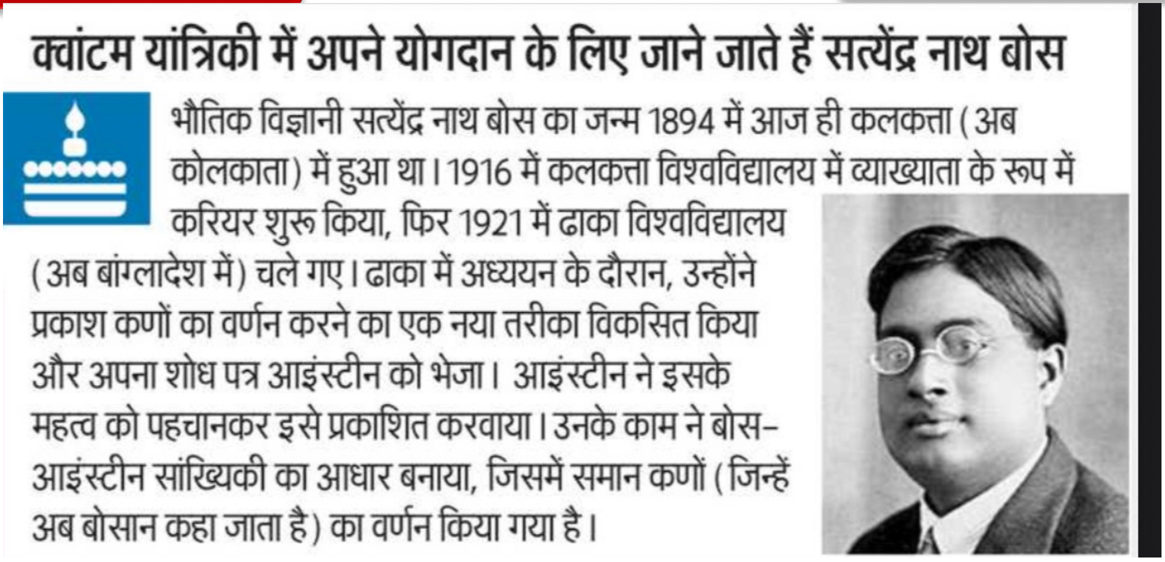

क्वांटम यांत्रिकी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं सत्येंद्र नाथ बोस

भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 में आज ही कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में करियर शुरू किया, फिर 1921 में ढाका विश्वविद्यालय (अब बांग्लादेश में) चले गए। ढाका में अध्ययन के दौरान, उन्होंने प्रकाश कणों का वर्णन करने का एक नया तरीका विकसित किया और अपना शोध पत्र आइंस्टीन को भेजा। आइंस्टीन ने इसके महत्व को पहचानकर इसे प्रकाशित करवाया। उनके काम ने बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का आधार बनाया, जिसमें समान कणों (जिन्हें अब बोसान कहा जाता है) का वर्णन किया गया है।

Dainik Jagaran Page No-14

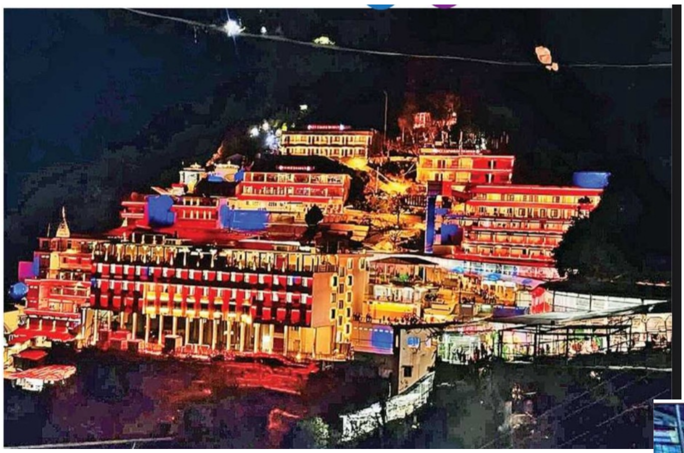

नव वर्ष
2026
की देशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ

EDU TERIA

Website : eduteriatestseries.com

साथी नया वर्ष आया है

रघोत्तम शुक्ल

काल अनंत है, किंतु सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति के अनुसार इसके विभाजक कालखंड तय किए गए हैं। इनमें वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने का समय होता है। इसे बारह भागों में विभक्त किया गया है, जो मास या महीना कहलाते हैं।

अंग्रेजी वर्ष या ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रचलित है तथा इस समय उपस्थित है। यह जनवरी से प्रारंभ होकर दिसंबर में पूर्ण होता है। पहले इसे रोमन कैलेंडर कहते थे, तब यह मार्च से शुरू होता था। इसलिए सितंबर से दिसंबर तक के महीनों के नाम संख्यावाची हैं, जो क्रमशः सातवें, आठवें, नौवें और दसवें महीने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बाद में इन लोगों ने जनवरी से वर्ष प्रारंभ कर दिया। यह उनके एक देवता 'जेनस' के नाम पर है, जिनके दो सिर एक-दूसरे से विपरीत दिशाओं में होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि एक वर्ष जा रहा है, दूसरा आ रहा है। फरवरी का नाम 'फेबुअस' नामक स्नान पर्व पर पड़ा। यह फरवरी के अंत में होता है। मार्च का नाम 'मार्स' या मंगल के नाम पर रखा गया। मार्स उनके युद्ध के देवता हैं, जो विश्वविजयी माने जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र भी मंगल को युद्धक ग्रह मानते हैं। अप्रैल 'एप्रिलियस' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'मुख खोलना' यानी प्रस्फुटन। इस समय वनस्पतियां लहलहाती और खिलती हैं। मई, जिसे वे 'मे' कहते हैं, उनकी फूलों की देवी का नाम है। उन्हीं के नाम पर इस मास का नामकरण हुआ। इस समय फूल खिले होते हैं। जून मास का नाम रोमन सम्राट 'जूनियस' के नाम पर रखा गया और जुलाई का नाम जूलियस सीजर सम्राट ने अपने तथा अपने पिता 'जूलियस' के नाम पर रखा। अगस्त का नाम रोम के प्रथम बादशाह 'आक्टेवियस अगस्टस' के नाम पर रखा गया।

> वर्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने का समय होता है

हिंदू भाई विक्रम संवत्सर को विशेष मान्यता देते हैं, जिसका संबंध सम्राट विक्रमादित्य की शकों पर विजय से है। यह ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यह चंद्र वर्ष है और इसके मास पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। इनके नाम भी पूर्णिमा को चंद्र के नक्षत्राचार से जुड़े हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया। महीने हैं- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन (क्वार), कार्तिक, मार्गशीर्ष (अगहन), पौष, माघ, फाल्गुन। इनकी पूर्णिमाओं को चंद्रमा क्रमशः चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रों पर होता है। वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। यह संवत्सर लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि पृथ्वी की एक सूर्य परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में होती है। अतः इस कैलेंडर में प्रति तीसरे वर्ष एक मलमास या अधिमास रखा जाता है।

(लेखक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

EDU TERIA

EDU TERIA

Website : eduteriatestseries.com

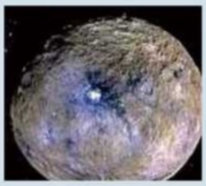

खगोलशास्त्री ग्यूसेप्पे पियाजी ने बौने ग्रह सेरेस की खोज की

1801 में आज ही इतालवी खगोलशास्त्री ग्यूसेप्पे पियाजी ने सिसिली में तारों की सूची बनाते समय बौने ग्रह सेरेस की खोज की थी। यह एस्ट्रायड बेल्ट में पाया जाने वाला पहला पिंड था, जिसे पहले ग्रह, फिर क्षुद्रग्रह माना गया और अंततः 2006 में बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया।

चेकोस्लोवाकिया चेक गणराज्य व स्लोवाकिया में विभाजित हो गया

1993 में आज ही चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक भंग होकर चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में विभाजित हो गया था। इस घटना को 'वेलवेट डाइवोर्स' के नाम से जाना जाता है। यह सौहार्दपूर्ण अलगाव चेक और स्लोवाक नेताओं के बीच बढ़ते राजनीतिक व आर्थिक मतभेदों का परिणाम था।

CZECH REPUBLIC
SLOVAK REPUBLIC

Dainik Jagaran Page No-14

मैग्नस कार्लसन ने रेकार्ड नौवां खिताब अपने नाम किया

एरिगैसी ने कांस्य जीता, पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

भारत के शीर्ष ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वह विश्व ब्लिट्ज में पदक जीतने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। वहीं विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अपना चिर परिचित खेल दिखाते हुए उजबेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को 2.5–1.5 से हराकर खिताब जीता।

एरिगैसी 19वें राउंड के क्वालीफिकेशन में 15 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, लेकिन सेमीफइनल में उन्हे अब्दुसत्तोरोव से 0.5–2.5 से हार मिली। वह इससे पहले भी विश्व रैपिड चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। कार्लसन ने कारूआना को 3.1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इससे पहले एरिगेसी ने कार्लसन और अब्दुसत्तोरोव जैसे धुरंधरों को हराकर पहला स्थान हासिल किया था। वह चार जीत और दो ड्रा के बाद शीर्ष पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने अब्दुसत्तोरोव को सोमवार को हराया था। हालांकि, सेमीफाइनल में एरीगैसी अपने लय को बरकरार नहीं रख सके और 47 चालों के बाद 0.1 से पीछे थे। दूसरा गेम 83 चालों में खत्म हुआ और तीसरा गेम ड्रा रखकर अब्दुसत्तोरोव ने फाइनल में जगह बनाई।

रेकार्ड नौवां खिताब जीतने के बाद कार्लसन ने बताया कि यह काफी कठिन टूर्नामेंट था और वह खुशकिस्मत रहे कि शुरुआती दौर के खराब प्रदर्शन से उबरकर नौवीं बार खिताब जीत सके। रैपिड और ब्लिट्ज दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कार्लसन ने फिडे से कहा, 'यह काफी कठिन टूर्नामेंट था और इसमें कोई भी जीत सकता था, लेकिन नाकआउट में पहुंचने के बाद मैंने अपने खेल का पूरा मजा लेकर खेला और इसका फायदा भी मिला।' इससे पहले कार्लसन को एरीगैसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल, नौवें दौर में कार्लसन के हाथ से मोहरा फिसल कर नीचे गिर गया था अर जब तक वे उसे उठाकर बोर्ड पर रखते, तबतक उक मय समाप्त हो चुका था। हालांकि, इस दौरान वे अपने गस्सिे को छिपा नहीं पाए और मेज को मुक्के से मारकर हिला दिया था।

महिला वर्ग में कजाखस्तान की बिबिसारा असायुबायेवा ने यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक को हराकर तीसरा विश्व ब्लिट्ज खिताब जीता। भारत की कोनेरू हंपी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2019 और 2024 में खिताब जीते थे।

विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप

एरिगैसी 19वें राउंड के क्वालीफिकेशन में 15 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे, लेकिन सेमीफइनल में उन्हे अब्दुसत्तोरोव से 0.5–2.5 से हार मिली। वह इससे पहले भी विश्व रैपिड चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। इससे पहले एरिगेसी ने कार्लसन और अब्दुसत्तोरोव जैसे धुरंधरों को हराकर पहला स्थान हासिल किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांस्य जीतने पर एरिगैसी की तारीफ की

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोहा में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे शतरंज में भारत के बढ़ते कद की बानगी मिलती है। एरिगैसी स्विस राउंड में 15 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। उन्होंने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव से 2.5–1.5 से हारकर तीसरे स्थान पर रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'शतरंज में भारत का दबदबा बरकरार। अर्जुन एरिगैसी को फिडे रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य के बाद दोहा में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य जीतने पर बधाई। उनका कौशल, जुनून और संयम असाधारण है। उनकी सफलता से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।'

Jansatta Page No-18

बेजिंग में हुई क्वाड देशों के राजदूतों की बैठक

बेजिंग, 31 दिसंबर (भाषा)।

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बेजिंग में सार्वजनिक रूप से प्रचारित दुर्लभ बैठक की। अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की और बताया यह बैठक बेजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में मंगलवार को हुई। परड्यू ने अपने 'पोस्ट' में कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में एक सकारात्मक शक्ति है।

Jansatta Page No-12

आज से कार की कीमतों में इजाफा, किसानों को ऋण सुविधा में राहत

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (ब्यूरो)।

एक जनवरी से देश में वित्तीय क्षेत्र में कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जिनका आम आदमी पर कमोबेश असर पड़ेगा। कारों की कीमतों में इजाफा होने का ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा तो किसानों को ऋण सुविधा में राहत प्रदान की गई है। ईपीएफओ पेंशन की निकासी के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा होगी लेकिन अब तक पैन-आधार को लिंक नहीं करने वालों के खाते पर पाबंदी या सेवाओं में बाधाएं पेश आ सकती हैं।

एक जनवरी से कारों की दरों में बढ़ोतरी की हुंदई, महिंद्रा और सजुकी सहित अन्य कंपनियों ने घोषणा कर दी है और यह दो से चार फीसद के बीच होगी। लागत में बढ़ोतरी की वजह से यह इजाफा किया जा रहा है। किसानों को ऋण देने और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ उनकी वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए अब किसानों को बिना गिरवी के 2 लाख रुपए तक के ऋण मिलेगा जो पहले 1.6 लाख रुपए था।

यूपीआइ के भुगतान और लेनदेन की सीमा में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इससे उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान में सहूलियतें बढ़ जाएंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन निकालने की प्रक्रिया भी आसान की जा रही है। इसके तहत पेंशनधारकों को किसी भी बैंक के एटीएम से पेंशन निकालने की सुविधा होगी। नए साल से क्रेडिट ब्यूरो, अब हर हफ्ते ग्राहकों के डेटा को अपडेट करना शुरू करेगा, जो पहले 15 दिनों बाद किया जाता था। क्रेडिट स्कोर में बदलाव से ऋण के लिए स्वीकृति आसान हो जाएगी और ब्याज दर में भी राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ बैंकों ने कर्ज पर ब्याज की दरें घटाई हैं, लेकिन जमा पर ब्याज दर में राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल भुगतान पर नजर रखने के लिए यूपीआइ लेनदेन पर भी निगरानी रहेगी। सिम के लिए सत्यापन के नियमों को सख्त किए जाने से धोखाधड़ी पर भी शिकंजा कसेगा।

उधर देश भर में पिछले एक दशक में ब्राडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या में छह गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस साल नवंबर में भारत में यह आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ के पार हो गया। नवंबर 2015 के अंत में ब्राडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 13.15 करोड़ थी जो इस साल नवंबर में बढ़कर 1 100.37 करोड़ यानी एक अरब से भी अधिक हो गया है।

Jansatta Page No-12

सरकारी आंकड़े जारी

राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 62.3 फीसद पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

केंद्र का राजकोषीय घाटा नवंबर के अंत तक 9.76 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट लक्ष्य का 62.3 फीसद है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले साल इसी समय यह 52.5 फीसद था।

केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा (व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) जीडीपी का 4.4 फीसद यानी 15.69 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान रखा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के अनुसार, नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार की कुल आय 19.49 लाख करोड़ रुपए रही, जो कुल बजट अनुमान का 55.7 फीसद है। इसमें से 13.94 लाख करोड़ रुपए कर राजस्व के रूप में मिले, 5.16 लाख करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व से प्राप्त हुए और 38,927 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के रूप में आए। इसी अवधि में केंद्र सरकार ने राज्यों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 9.36 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 1.24 लाख करोड़ रुपए अधिक है। नवंबर तक केंद्र सरकार का कुल खर्च 29.26 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वार्षिक बजट अनुमान का 57.8 फीसद है। इसमें से 22.67 लाख करोड़ रुपए राजस्व मद में और 6.58 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत मद में खर्च किए गए। राजस्व खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान का रहा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार की कुल आय 19 .49 लाख करोड़ रुपए रही, जो कुल बजट अनुमान का 55 .7 फीसद है।

Jansatta Page No-10

यूरोपीय संघ का कार्बन कर आज से, भारत को होगा नुकसान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

यूरोपीय संघ (ईयू) का कुछ धातुओं पर कार्बन कर (सीबीएएम) एक जनवरी से लागू होने जा रहा है जिससे भारत के इस्पात एवं एल्युमीनियम निर्यात को झटका लग सकता है। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआइ ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यूरोपीय संघ के 27 देशों का समूह उन वस्तुओं पर यह कर लगा रहा है जिनके निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन होता है। इस्पात क्षेत्र में ब्लास्ट फर्नेसझ्रबेसिक आक्सीजन फर्नेस (बीएफझ्रबीओएफ) मार्ग में उत्सर्जन सबसे अधिक होता है जबकि गैस आधारित डीआरआइ में यह कम तथा कबाड़ (स्क्रैप) आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) में सबसे कम होता है। इसी तरह एल्युमीनियम में बिजली का स्रोत एवं ऊर्जा की खपत अहम भूमिका निभाती है। कोयले से उत्पादित बिजली से कार्बन बोझ बढ़ता है जिससे सीबीएएम लागत भी अधिक होती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) के अनुसार, कई भारतीय निर्यातकों को कीमतों में 15 से 22 फीसद तक की कटौती करनी पड़ सकती है ताकि ईयू के आयातक उसी मुनाफे (मार्जिन) से सीबीएएम कर का भुगतान कर सकें। भारतीय निर्यातकों को सीधे तौर पर कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूरोपीय संघ स्थित आयातकों (जो अधिकृत सीबीएएम घोषणाकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं) को आयातित वस्तुओं में निहित उत्सर्जन से संबंधित सीबीएएम प्रमाणपत्र खरीदने होंगे। इसका भार अंततः भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, '' एक जनवरी 2026 से ईयू में प्रवेश करने वाली भारतीय इस्पात एवं एल्युमीनियम की हर खेप पर कार्बन लागत जुड़ेगी क्योंकि सीबीएएम 'रिपोर्टिंग' चरण से भुगतान चरण में प्रवेश करेगा।'

भारतीय इस्पात, एल्युमीनियम निर्यातकों को नुकसान की आशंका।

Jansatta Page No-10

भारत से रूस को वस्त्र निर्यात बढ़ने की उम्मीद

अमेरिकी शुल्क के कारण 25 हजार करोड़ सालाना का बाजार पड़ा ठप

आशीष दुबे
नोएडा, 31 दिसंबर।

वर्ष 2026 नोएडा के वस्त्र निर्यातकों के लिए राहत लेकर आ सकता है। अमेरिकी शुल्क बढ़ने के बाद जिस तरह यहां के कारोबारियों पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के निर्यात बाजार का संकट खड़ा हुआ था, उसकी भरपाई में रूस का बाजार अहम भूमिका निभा सकता है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद से वस्त्र निर्यातकों को सकारात्मक संकेत मिले हैं।

हालांकि अमेरिकी बाजार की तुलना में रूस भारतीय वस्त्र निर्यातकों के लिए उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका को होने वाला निर्यात लगभग ठप पड़ने के बाद यदि कुछ हजार करोड़ रुपए का निर्यात भी रूस को बढ़ता है, तो इससे नोएडा की कई इकाइयों में संभावित छंटनी और बंदी के खतरे को कम किया जा सकेगा।

पुतिन के दौरे के बाद वस्त्र निर्यातकों को दो हजार करोड़ के कारोबार की है उम्मीद।

नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के महासचिव राजीव बंसल ने जनसत्ता से बातचीत में बताया कि जनपद में करीब आठ हजार से अधिक रेडीमेड कपड़े बनाने की कंपनियां हैं, जिनमें सीधे और परोक्ष रूप से करीब दस लाख लोग जुड़े हुए हैं। इन कंपनियों से सालाना करीब 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक के वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। जिनका चालीस फीसद, करीब 25 हजार करोड़ रुपए का अकेले अमेरिका को निर्यात होता था। ट्रंप सरकार के भारत पर ज्यादा शुल्क लगाए जाने से वस्त्र समेत भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे हो गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर नोएडा के वस्त्र उद्योग पर पड़ा है। रूस में करीब सात अरब डालर मूल्य के वस्त्रों का निर्यात करता है। जिसमें भारत की भागीदारी केवल डेढ़ फीसद के आसपास है। पुतिन के साथ पिछले दिनों हुई बातचीत के बाद निर्यात प्रोत्साहन परिषदों ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के समझौतों का असर इस साल दिखाई देगा। जिसके कारण करीब दो हजार करोड़ रुपए तक के वस्त्रों का निर्यात रूस को इस साल होने की उम्मीद है।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि रूस से भारत का व्यापार घाटा करीब 59 अरब डालर का है। भारत से रूस को साढ़े चार अरब डालर का सामान आयात किया जाता है। जबकि रूस, भारत को करीब 64 अरब डालर का निर्यात करता है।

Jansatta Page No-4

छोटे जिलों में नवाचार के लिए आइआइटी दिल्ली में नई पहल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के एफआइटीटी ने छोटे जिलों में नवाचार के माहौल को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल की। इसके लिए देश के सबसे बड़े शिक्षक-केंद्रित और शोध-आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस पहल को ब्लाकचेन फार इम्पैक्ट के माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 35 शैक्षणिक संस्थानों के 63 शिक्षकों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी भारत के 25 जिलों से आए थे। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, पशु चिकित्सा, कानून और प्रबंधन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के कालेज शामिल थे। शिक्षक लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर और बुलंदशहर जैसे शहरों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर के संस्थानों से भी आए थे।

यह कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया था कि शिक्षकों के माध्यम से 1.35 लाख से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जा सके। यह एक अनोखा आयोजन रहा, जिसमें इन संस्थानों की भागीदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के सहयोग से संभव हो पाई।

Jansatta Page No-2

जयशंकर के साथ भेजे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान से कहा

खालिदा की दूरदृष्टि हमारी साझेदारी का मार्गदर्शक बनेगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक प्रकट किया।

ढाका में जयशंकर ने तारिक रहमान से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा, 'भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त। विश्वास है कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य हमारी साझेदारी के विकास में मार्गदर्शक बनेंगे।' पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचने के तुरंत बाद जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान से मुलाकात की और तीन दशकों से अधिक समय तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली इस नेता के निधन पर भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की।

बारह फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले रहमान से मुलाकात के दौरान, जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि जिया का 'दृष्टिकोण और मूल्य' दोनों देशों के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर अपनी

बाकी पेज ८ पर

Jansatta Page No-1

सकारात्मक

आरबीआइ ने जारी की 'वित्तीय स्थिरता रपट'

मजबूती से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

वैश्विक आर्थिक माहौल चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत वृद्धि बनाए रखने की संभावना है और इसे मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति एवं संतुलित व्यापक आर्थिक नीतियों से समर्थन मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बुधवार को अपनी रपट में यह बात कही।

आरबीआइ ने अपनी 'वित्तीय स्थिरता रपट' (एफएसआर) में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक

बाकी पेज ८ पर

बैंकों का एनपीए मार्च 2027 तक घटकर 1.9 फीसद रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (ब्यूरो)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात में आगे भी सुधार जारी रहने की संभावना है और मार्च 2027 तक यह घटकर 1.9 फीसद रह सकता है। यह अनुमान सामान्य परिस्थितियों के आधार पर लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रपट में बताया कि सितंबर 2025 तक सकल एनपीए अनुपात 2.1 फीसद पर आ गया था, जो कई दशकों का निचला स्तर है। रपट के अनुसार, 46 बैंकों का संयुक्त सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2025 के 2.1 फीसद से घटकर मार्च 2027 में 1.9 फीसद हो सकता है। हालांकि, यदि आर्थिक स्थिति प्रतिकूल रहती है, तो यह अनुपात 3.2 फीसद से 4.2 फीसद तक बढ़ सकता है।

पूंजी की स्थिति पर रपट में कहा गया है कि बैंकों में पूंजी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर) के पास नुकसान सहने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद है। सितंबर 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में यह 16 फीसद और निजी बैंकों में 18.1 फीसद है। इससे बैंक आर्थिक झटकों का सामना कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार, यदि आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाते हैं, तो भी अधिकांश बैंक टिके रह सकते हैं।

Jansatta Page No-1

राजकोषीय घाटा नवंबर में बजट अनुमान के 62.3% पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

केंद्र का राजकोषीय घाटा नवंबर के अंत तक 9.76 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट लक्ष्य का 62.3 फीसद है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले साल इसी समय यह 52.5 फीसद था। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा (व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) जीडीपी का 4.4 फीसद यानी 15.69 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान रखा है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार की कुल आय 19.49 लाख करोड़ रुपए रही, जो कुल बजट अनुमान का 55.7 फीसद है।

-पूरी खबर पेज 10

Jansatta Page No-1

डीआरडीओ ने एक ही लांचर से दागीं दो प्रलय मिसाइलें

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी तौर पर विकसित 'प्रलय' मिसाइलों के लगातार दो सफल परीक्षण किए। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लांचर से दो मिसाइलों को बैक-टु-बैक फायर किया। युद्ध की स्थिति में यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है। जब दुश्मन की तरफ एक साथ दो या उससे ज्यादा मिसाइलें एक ही लक्ष्य या अलग-अलग लक्ष्यों की ओर बढ़ती हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम (रक्षा प्रणाली) के लिए उन्हें एक साथ रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर दुश्मन एक मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है तो दूसरी मिसाइल अपना काम कर जाती है।

प्रलय का यह 'डबल अटैक' दुश्मन के बंकरों, एयरबेस और रणनीतिक ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित 'प्रलय' मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन नमूना है।

प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ की हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला ने विकसित किया है। इसके अलावा इसमें डीआरडीओ की कई अन्य प्रयोगशालाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना, वायुसेना और मिसाइल निर्माण से जुड़े संस्थानों तथा विज्ञानियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक (साल्वो) लांच की सफलता ने 'प्रलय' मिसाइल की विश्वसनीयता को स्थापित कर दिया है।

- दुश्मन पर एक साथ बैक टु बैक फायर होने वाली मिसाइलें मचाएंगी तबाही
- रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का बेहतरीन नमूना है यह मिसाइल

ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल। एएनआइ

उड़ान के दौरान रास्ता बदलकर प्रहार करने में सक्षम

प्रलय एक 'क्वासी-बैलिस्टिक' मिसाइल है, जो उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल कर दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह आखिरी समय में भी चकमा देकर दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल है। परीक्षण के दौरान दोनों मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदा और परीक्षण मिशन के सभी उद्देश्यों को शत-प्रतिशत पूरा किया। यह सफल परीक्षण प्रलय मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षण भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक ताकत को और मजबूत करने की दिशा में अहम है।

150 से 500 किलोमीटर तक है मिसाइल की मारक क्षमता

इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 350 से 1000 किलोग्राम तक पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें कवच रोधी वारहेड भी शामिल है। इससे सैन्य बलों की ताकत और बढ़ेगी।

ठोस ईंधन का उपयोग

इस मिसाइल में सालिड प्रोपेलेंट (ठोस ईंधन) का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के मैदान में लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सालिड फ्यूल वाली मिसाइलें 'रेडी-टू-फायर' मोड में होती हैं। इन्हें बहुत कम समय में लांच किया जा सकता है, जो आक्रामक कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी है।

मिसाइल का विकास पूरा, यह परीक्षण 'यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स' का हिस्सा

यह परीक्षण 'यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स' का हिस्सा था। इसका मतलब यह है कि मिसाइल का विकास पूरा हो चुका है और अब सेना इसे अपनी कसौटी पर परख रही है, ताकि इसे औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया जा सके। परीक्षण के मौके पर वायुसेना और सेना के अफसर भी उपस्थित थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष डा. समीर वी कामत ने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि यह सिस्टम अब सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह परीक्षण भारत की रक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह बताता है कि अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और सटीक मारक क्षमता विकसित कर रहा है।

Dainik Jagaran Page No-1

बेजिंग में हुई क्वाड देशों के राजदूतों की बैठक

बेजिंग, 31 दिसंबर (भाषा)।

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बेजिंग में सार्वजनिक रूप से प्रचारित दुर्लभ बैठक की। अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की और बताया यह बैठक बेजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास में मंगलवार को हुई। परड्यू ने अपने 'पोस्ट' में कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में एक सकारात्मक शक्ति है।

शंघाई में बैठे सर्जन ने मुंबई में किया आपरेशन

- पहली बार रोबोटिक सर्जरी का दावा
- रेडिकल प्रोस्टेटेक्टामी व पार्शियल नेफ्रेक्टामी की सर्जरी की गई

भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई रिमोट रोबोटिक सर्जरी। एक्स

मुंबई, प्रेट्र : यह विज्ञान का एक और चमत्कार है। चीन के शंघाई शहर से एक सर्जन ने मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती दो मरीजों का पांच हजार किलोमीटर की दूरी पर बैठे-बैठे आपरेशन कर दिया। अस्पताल ने दावा किया कि यह भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई रिमोट रोबोटिक सर्जरी थी।

मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर टूमाई रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उपयोग करके रेडिकल प्रोस्टेटेक्टामी और पार्शियल नेफ्रेक्टामी की सर्जरी की गई। टूमाई एक अत्याधुनिक रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है, जिसके जरिये डाक्टर हजारों किलोमीटर दूर से भी जटिल आपरेशन कर सकते हैं। इसमें 3डी एचडी विजुअलाइजेशन और 5जी/ब्राडबैंड जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे सर्जरी में लगने वाला समय कम होता है और मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है। यह आपरेशन अत्याधुनिक डाटा संचरण तकनीक पर आधारित था, जिसमें मात्र 132 मिली सेकंड का विलंब हुआ। अस्पताल के अनुसार, तात्कालिक कनेक्शन ने उपकरणों की निर्बाध आवाजाही और सटीक आपरेशन को संभव बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शल्यक्रियाएं पारंपरिक प्रक्रियाओं जितनी ही सुरक्षित और विश्वसनीय थीं। इन प्रक्रियाओं का नेतृत्व शंघाई में बैठकर डा. टीबी युवराज ने किया, जिनके पास 4,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी का अनुभव है। वह कोकिलाबेन अस्पताल में यूरो-आन्कोलाजी और रोबोटिक सर्जरी के निदेशक हैं। सर्जरी पूरी करने के बाद डा. युवराज ने कहा कि रिमोट रोबोटिक सर्जरी में उच्च गुणवत्ता वाली शल्यक्रिया उपलब्ध कराने की क्षमता है। दो बड़े देशों में इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने से भारत और दुनियाभर में विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के नए रास्ते खुलेंगे। इस उपलब्धि ने न केवल भारत में एक नया अध्याय खोला है, बल्कि यह अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।

Dainik Jagaran Page No-14

मार्गदर्शन : दूसरों को सिखाते हुए स्वयं को निखारने की प्रक्रिया

परामर्श

मार्गदर्शन देना केवल किसी को सही रास्ता दिखाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह स्वयं के व्यक्तित्व और कौशल को विकसित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन करता है, तो वह हर संवाद के माध्यम से अपने अनुभवों की समीक्षा करता है और नई सीख प्राप्त करता है। मार्गदर्शन लेने वाले के सवाल, उनकी चुनौतियां और सोच, मार्गदर्शक को अपने नेतृत्व व दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का अवसर देती हैं। मार्गदर्शन एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों के लिए लाभकारी बन जाता है।

नियमित बातचीत मार्गदर्शक और मार्गदर्शन लेने वाले के बीच विश्वास की नींव रखती है। जब आप लगातार किसी के विचारों, समस्याओं और प्रयासों को सुनते हैं, तो उनकी मानसिकता और जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। इससे न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि अलग-अलग व्यक्तित्वों के साथ काम करने की क्षमता भी विकसित होती है। यह समझ आगे चलकर बेहतर निर्णय लेने में सहायक बनती है।

अच्छा मार्गदर्शन तभी संभव है जब सुनने की क्षमता मजबूत हो। बिना टोके, ध्यानपूर्वक और खुले मन से सुनना सामने वाले को महत्व देने का एहसास कराता है। इससे आप उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को सही ढंग से समझ पाते हैं। समय के साथ यह आदत आपको रचनात्मक और ईमानदार प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। साथ ही, दूसरों से मिलने वाले फीडबैक को स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित होती है, जो आत्म-जागरूकता को बढ़ाती है। मेंटी अक्सर नए विचारों, आधुनिक सोच और अलग अनुभवों के साथ आते हैं। उनसे बातचीत करते हुए आप भी अपनी सोच को नया आयाम देते हैं।

पति की कब्र के पास दफनाई गईं बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया

पूर्व पीएम के जनाजे में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, भावभीनी विदाई दी

राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, कल हुआ था निधन

ढाका में बुधवार को संसद भवन के पास बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ का हवाई दृश्य। एएफपी

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया। जिया के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें भावभीनी विदाई दी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं जिया का मंगलवार को निधन हो गया था। वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार थीं।

खालिदा जिया के ताबूत को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था और इसे उनके आवास से अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग संसद परिसर के बाहर एकत्रित हुए, जिन्होंने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक जिया की तस्वीरों वाले झंडे लेकर आए थे, जो उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, चीफ जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी और जिया के बेटे व बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान भी जनाजे की नमाज में शामिल हुए। तारिक ने नमाज से पहले वहां मौजूद लोगों से कहा, 'कृपया अल्लाह से दुआ करें कि उन्हें जन्न में जगह मिले।'

बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रहीं जिया की नमाज-ए-जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समाज के हर वर्ग से आए शोक संतप्त लोगों ने जिया के आत्मा की शांति के लिए दुआ की। नमाज के बाद स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे संसद भवन परिसर के समीप जिया को उनके पति की कब्र के पास दफनाया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, जिया के अंतिम संस्कार में 33 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजदूत, उच्चायुक्त और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल थे। यह दर्शाता है कि जिया का प्रभाव केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान थी।

बीएनपी नेता तारिक रहमान से मिले जयशंकर, पीएम मोदी का पत्र सौंपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ढाका में पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विदेश मंत्री
- पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सादिक से भी हुई जयशंकर की भेंट
- भारत-बांग्लादेश संबंधों के नए अध्याय की होगी शुरुआत: रियाज हमीदुल्लाह

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर बुधवार को ढाका में उनके पुत्र और बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शोक संदेश सौंपते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

क्या पूर्व पीएम खालिदा जिया की मौत और उसके बाद भारत सरकार की संवेदनशील प्रतिक्रिया भारत और बांग्लादेश के लगातार खराब होते संबंधों पर विराम लगा सकते हैं? इस बारे में स्पष्ट आकलन तो मुश्किल होगा लेकिन जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर की शिरकत और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के नाम पीएम नरेन्द्र मोदी का व्यक्तिगत पत्र कुछ ऐसा संकेत देता है। जयशंकर ने तारिक से मुलाकात कर भारत सरकार व भारत की जनता की तरफ से पूर्व पीएम की मौत पर अपना शोक व संवेदनाएं प्रकट कीं। साथ ही उन्हें पीएम मोदी का व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा।

ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जयशंकर की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अजीज सादिक से मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई है। जयशंकर बुधवार सुबह 11.30 बजे (स्थानीय समय) भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से ढाका पहुंचे। वहां उनका स्वागत बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सचिव फरहद होसैन ने किया।

जयशंकर ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, 'ढाका पहुंचने पमें बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष व पूर्व पीएम के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान तारिक के साथ पार्टी के तकरीबन सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जबकि भारतीय Dnnल में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी शामिल थे। संकेत हैं कि जयशंकर की बीएनपी नेताओं के साथ मुलाकात भले संक्षिप्त रही, लेकिन इसमे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा हुई।

'आपके नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों की नई शुरुआत'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पीएम मोदी ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष व पूर्व पीएम स्वर्गीय खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान को लिखे विशेष पत्र में जिया की मौत पर न सिर्फ भारत की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट की है बल्कि भारत व बांग्लादेश के संबंधों में मौजूदा तनाव को दूर करने की बड़ी पेशकश भी कर दी है। पीएम मोदी ने 2015 में खालिदा जिया के साथ मुलाकात को याद किया है, भारत-बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को बनाने में उनके योगदान की तारीफ की है और साथ ही तारिक से उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में नए युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है, 'आपकी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर मुझे दुख हुआ। वह बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थीं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। मुझे 2015 में ढाका यात्रा के दौरान उनसे मिलने और बातचीत याद है। उनकी रिक्तता को पूरा करना मुश्किल है, लेकिन उनका दृष्टिकोण व परंपरा जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अपनी अगुआई में आप उनके आदर्शों को आगे ले जाएंगे।'

Dainik Jagaran Page No-11

बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नए वर्ष 2026 के आगमन से ठीक पहले आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि आगामी वर्ष अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहेगा, लेकिन भारतीय इकोनमी और वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। आरबीआइ ने बुधवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) यह बात कही। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा, 'वर्ष 2025 का वर्ष भू-राजनीतिक संघर्षों, व्यापार तनाव और नीतिगत अनिश्चितताओं से चुनौतीपूर्ण रहा और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर भी दिखाई दिया। हालांकि, इसके बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था अपेक्षा से अधिक मजबूत साबित हुई और वित्तीय प्रणाली भी स्थिर रही। हालांकि, 2026 और उसके बाद की स्थिति अनिश्चितताओं से भरी साबित हो सकती है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करने वाली शक्तियां अभी स्थिर नहीं हुई हैं।'

- आरबीआइ गवर्नर ने कहा-वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करने वाली शक्तियां अभी स्थिर नहीं हुई
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-2025 में आगे भी भारत की तेज आर्थिक विकास दर बने रहने की उम्मीद जताई गई
- इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत 30 सितंबर, 2025 तक ऋणदाताओं ने चार लाख करोड़ रुपये वसूले

एफएसआर-2025 में कहा गया है कि भारत की तेज आर्थिक विकास दर आगे भी बनी रहेगी। आरबीआइ गवर्नर ने अपने बयान में कहा, 'अस्थिर और प्रतिकूल बाहरी वातावरण के बावजूद, घरेलू खपत और निवेश से प्रेरित उच्च विकास दर्ज करने की उम्मीद है।' रिपोर्ट में घरेलू मांग में हो रही वृद्धि, महंगाई दर के लगातार नीचे बने रहने की संभावना और लगातार सुधारवादी आर्थिक नीतियों को तेज विकास दर का श्रेय दिया गया है। साथ ही देश के वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति मजबूत बनी हुई है, बैंकों ने फंसे कर्जे (एनपीए) की समस्या को काफी हद तक काबू कर लिया है। नए एनपीए बनने की रफ्तार भी काफी कम हुई है, जो वित्तीय ढांचे के दीर्घावधि में सुरक्षित बने रहने का संकेत दे रहे हैं।

सरकार पर बढ़ते कर्ज को जोखिम के तौर पर चिह्नित किया

आरबीआइ गवर्नर ने कुछ जोखिमों की तरफ भी इशारा किया है, जिसमें वित्तीय सेक्टर की कुछ संपत्तियों का ऊंचा मूल्यांकन भी एक है। संभवत: यह इशारा भारतीय शेयर बाजार की तरफ है, जहां कुछ सेक्टरों में अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी देखी गई है। उन्होंने सरकार पर बढ़ते कर्ज, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच लगातार संबंद्धता बनने को भी एक जोखिम के तौर पर चिह्नित किया है।

वित्तीय प्रणाली को मजबूत रखना आरबीआइ का लक्ष्य

मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना आरबीआइ का मुख्य लक्ष्य है, लेकिन यह अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। नवाचार और विकास को बढ़ावा देना, उपभोक्ता संरक्षण के साथ कुशल नियमन एवं पर्यवेक्षण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कहा, 'नीति निर्माताओं का सबसे बड़ा योगदान एक ऐसी वित्तीय प्रणाली विकसित करना है जो बाहरी झटकों के प्रति मजबूत हो, वित्तीय सेवाएं प्रदान करे।'

Dainik Jagaran Page No-10

हिमाचल प्रदेश डायरी

लोकसेवाओं में व्यवहार के अंक

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

'क्या बताऊं, आपकी बच्ची को क्या हुआ है। जन्म लेते ही सांस रुका था कुछ देर के लिए...अभी तो उसे दौरे पड़ेंगे...लगता नहीं कि ठीक होगी। ठीक हो भी गई तो दिमाग काम नहीं करेगा! चुपचाप बैठो!' सामने से एक नर्स विश्व की क्रूरतम हंसी हंसते हुए निकल गई थी। करीब 12 वर्ष पूर्व यह दृश्य तब का है जब डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज अस्पताल टांडा में पिता बने चिंतित व्यक्ति ने बहुत विनम्रता, शालीनता के साथ डाक्टर साहब से नर्सरी में दाखिल तीन दिन की बेटी का हाल पूछा था। वह पिता कुछ अच्छे डाक्टरों के कारण और कुछ अपनी बेटी के भले के लिए खून का घूंट पी कर रह गया था।

2025 के अंत में यह घटना इसलिए कौंधी, क्योंकि संभव है 2026 में हिमाचल प्रदेश के चिकित्सक मानव व्यवहार और मनुष्य प्रबंधन का कोर्स पढ़ें। यह भी आशा है कि रोगी के साथ डाक्टर का व्यवहार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में मानक बने। ऐसे आदेश मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दिए हैं। चिकित्सा संस्थानों में मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि अमन काचरू कांड किसी मेडिकल कालेज में ही हुआ था। कोलकाता का आरजी कर अस्पताल चर्चा में क्यों रहा, किससे छिपा है। ये मानक इसलिए अनिवार्य हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल के एक वीडियो में डाक्टर आक्सीजन लगे एक रोगी पर मुक्के बरसा रहा था और बिस्तर पर लेटा हुआ रोगी भी डाक्टर पर लात चला रहा था। कौन गलत, कौन सही, इस पर हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी कर चुका है। दोनों पक्षों ने 30 दिसंबर की शाम को एक वीडियो में 'एक दूसरे को माफ किया' कह कर सार्वजनिक गले मिलन समारोह संपन्न कर लिया है, इसलिए निर्णय की आवश्यकता नहीं। डाक्टर थे सीनियर रेजिडेंट राघव निरूला और 'तू' कह देने पर भड़के रोगी थे अर्जुन पंवार।

उस मामले का सुखद अंत हो गया जिसने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को ही प्रभावित नहीं किया, चिकित्सक-रोगी संबंधों और प्रशासनिक सतर्कता पर नई बहस भी छेड़ी। डाक्टर बहाल हो जाएगा, किंतु यह प्रश्न रहेगा कि 'तू-तड़ाक' से आरंभ हुआ यह प्रकरण पहले ही समाप्त हो जाता तो अस्पतालों में रोगियों को आहें न भरनी पड़ती, वे ओपीडी, आपरेशन से वंचित न रहते।

न्यूरोसर्जन और भरमौर से विधायक डा. जनक राज कहते हैं, 'सारा विषय ही अहंकार का था। मेरे अधिसंख्य रोगी ऐसे होते थे जिनसे मैं संतुलित व्यवहार की आशा ही नहीं रख सकता था। एक बार एक रोगी ने थूका था मुझ पर...। मरीज की मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। दुख यही है कि जिस प्रशासन को अपने स्तर पर दोनों पक्षों को बैठा कर बात समाप्त करवानी थी, उसकी उदासीनता से छोटा सा प्रकरण मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया।'

जब किसी से कुछ प्रबंधित नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांग कर सीनियर रेजिडेंट को बर्खास्त कर दिया। कोई भी उस वीडियो को देख कर क्या निर्णय लेता? जब रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलने गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा जांच करवा लेते हैं। इसके बावजूद डाक्टर हड़ताल पर गए। जब डाक्टर का मुक्के बरसाने वाला वीडियो लोगों ने देखा तो कार्रवाई की मांग हुई और जब कार्रवाई हुई तो कहा कि एकपक्षीय है। सच यह है कि सब असफल थे, इसलिए मुख्यमंत्री सामने आए और जो ठीक लगा वह किया। मुख्यमंत्री का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है कि डाक्टरों को व्यवहार का पाठ पढ़ाया जाए। यही पाठ प्रदेश के अन्य अधिकारियों को भी पढ़ाया जाए, जो अन्यथा जनकार्यों के लिए समझे जाते हैं। यह विषय केवल चिकित्सक-रोगी संबंधों का नहीं, प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनहीनता का भी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल में अधीक्षक एवं उनकी टीम होती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के निदेशक होते हैं, स्वास्थ्य सचिव होता है। कारण पता नहीं, किंतु ये सब निष्क्रिय रहे। स्वास्थ्य मंत्री भी मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा करते रहे। मोर्चा सीधे मुख्यमंत्री सुक्खू को संभालना पड़ा। स्पष्ट है नीचे की सारी पंक्ति बेअसर रही। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्हें बड़े मुद्दों पर प्रदेश का भाग्य लिखने दिया जाना चाहिए।

संदर्भ प्रशासन का है तो जिलों का प्रशासन भी देखा जा सकता है। प्रसंगवश, कभी यह कहावत बहुत प्रसिद्ध होती थी कि देश में तीन ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं-पीएम, सीएम और डीएम। इनमें दो तो मौजूद हैं, किंतु तीसरा कहीं गुम हो गया है। वह सरकारी पत्रों में एंड वेयरएज आई...आइएएस... करने तक रह गया है। कभी वह कार्निवाल की भव्यता में श्रीवृद्धि कर रहा होता है तो कभी इस उधेड़बुन में होता है कि कार्निवाल के लिए चार करोड़ रुपये कहां से आएंगे। वह भी तब, जब प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। शिमला और धर्मशाला में कार्निवाल हो, अच्छी बात है, किंतु यहां तो पर्यटक तब भी आते हैं जब आप कार्निवाल न कर रहे हों। बहरहाल डाक्टर, अधिकारी, इंजीनियर, पत्रकार...सब समाज से आते हैं, सोचना तो यह भी होगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। प्रार्थना है...2026 कुछ भिन्न हो।

आओ, सब भुला दें : इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में लात घूंसा प्रकरण के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ने वाले डाक्टर राघव निरूला (बाएं, चश्मा पहने हुए) और मरीज अर्जुन पंवार (दाएं) एक दूसरे को माफ कर देने की घोषणा के दौरान। वीडियोग्रैब

Dainik Jagaran Page No-9

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था- टेली परफार्मेंसेज से संबद्ध

आजकल

नए साल में एआइ की बढ़ेगी चाल

हम इक्कीसवीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पार कर चुके हैं। समय अब वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहा है। यह केवल कैलेंडर का नया पन्ना नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य की दिशा तय करने वाला पड़ाव बनता दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीव्र और आक्रामक विस्तार को तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। यदि एआइ के इस विस्तार को बिना नियंत्रण के बढ़ने दिया गया तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका परिणाम अंततः मानव सभ्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है

AGRICUTURE
AI
AI
FINARAL CITIES
Ah
MANUFCLTING

एआइ आधारित भविष्य की दहलीज पर खड़ी दुनिया। प्रतीकात्मक

औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद मानव सभ्यता के ढाई सौ साल के सफर में मशीनों, तकनीकों और कारखानों के ज्यादातर दौर में विकास ने इंसानी हाथ के काम में ही हिस्सेदारी की है। भाप के इंजन और कताई की मशीनों से लेकर खेती के उपकरणों-यंत्रों ने एक तरह से हमारे काम में हाथ ही बंटाया है और श्रम की लागत को कम किया है, लेकिन पहले कंप्यूटर-इंटरनेट और फिर एआइ के विकास ने इंसानी दिमाग को बेदखल करने का प्रयास किया है। इस बदलाव की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए कि पृथ्वी पर इंसान अपनी दिमागी क्षमताओं के बल पर ही दूसरे जीवधारियों से आगे निकल सका है और उन पर अपनी बादशाहत कायम कर सका है। ऐसे में यदि इंसानी मस्तिष्क एआइ के आगे नत-मस्तक हो गया तो निश्चय ही कायनात पर हमारी पकड़ कमजोर होगी और जिस डरावने भविष्य का खाका खींचा जा रहा है, आशंका है कि वे बुरे सपने सच साबित हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर वे चुनौतियां क्या हैं, जो एआइ के जरिये सामने आ रही हैं और उनका सामना कैसे किया जा सकेगा?

तकनीक पत्रिका 'वायर्ड' ने "वर्ष 2026 के लिए एआइ की छह भयावह भविष्यवाणियां" शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एआइ तकनीक जिस उन्मादी गति से बढ़ रही है, वह सिर्फ रोजगार ही नहीं हड़पेगी, बल्कि कई स्तरों पर नई आपदाएं पैदा कर देगी। पहला है व्यक्तिगत गोपनीयता का क्षरण और दूसरा, विभिन्न देशों-महाद्वीपों के बीच अंतरराष्ट्रीय तनाव। एक मनुष्य की निजता या व्यक्तिगत गोपनीयता को पिछले दो-ढाई सौ साल के इतिहास में ज्यादा खतरा इसलिए नहीं था, क्योंकि एनालाग तकनीक के उस दौर में हर व्यक्ति की पहचान आम तौर पर तब तक सुरक्षित रहती थी, जब तक कि वह व्यक्ति खुद अपने विवरण और दस्तावेज दूसरों से साझा नहीं करता था, लेकिन पहले डिजिटल तकनीकों का विकास और फिर एआइ का आक्रमण-तकनीक की तेज तरक्की ने ऐसे-ऐसे विकल्प पैदा कर दिए हैं कि दुनिया के दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति और एआइ से लैस मशीनें (टूल्स) आपके बिना चाहे भी आपकी पहचान चोरी कर सकती हैं और उनका इस्तेमाल दूसरों को ठगने सहित तमाम आपराधिक कृत्यों में कर सकती हैं। डीपफेक के जरिये आज अगर हजारों लोगों को ठगा जा रहा है तो इसमें बड़ी भूमिका एआइ तकनीकों की है, क्योंकि उनके इस्तेमाल से असली और नकली का फर्क मिट गया है।

अंतरराष्ट्रीय तनावों की जड़ : अंतरराष्ट्रीय तनावों से जुड़ा दूसरा खतरा भी एआइ के बढ़ते प्रभुत्व की देन है। एआइ-प्रेरित डीपफेक और एल्गोरिदम जैसी तकनीकों ने झूठे प्रचार को इतना वास्तविक बना दिया है कि लोग उसे सच मान लेते हैं और महाशक्तियों के फैलाए जाल में उलझ जाते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने साबित किया है कि एल्गोरिदम और डीपफेक अब जंग के नए हथियार हैं, जिनमें एआइ ने नई छौंक लगा दी है। एआइ के भयावह भविष्य की ये चेतावनियां काल्पनिक नहीं हैं। इसे इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2025 में इस तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण दुनिया भर में लाखों नौकरियां गई हैं। सिर्फ आईटी ही नहीं, उन सभी सेक्टरों में नौकरियों में छंटनी का नया दौर शुरू हुआ है, जहां एआइ की मदद से कुछ काम किए जा सकते हैं। कहने को तो उन तकनीकी कंपनियों में नए अवसर पैदा हुए हैं, जो एआइ के कामकाज से संबंधित हैं, जैसे कि ओपनएआइ और एनवीडिया, लेकिन गूगल से लेकर इन्फोसिस में हुई छंटनी साबित करती है कि खुद आधुनिक तकनीक से जुड़ी कंपनियों का कामकाज इंसानी हाथों से निकलकर एआइ-संचालित चैटबाट के हिस्से में जाने वाला है, क्योंकि इन कंपनियों के मालिक अपने मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं।

डाटा सेंटरों से पैदा होता खतरा : एआइ से जुड़ा एक अस्तित्वगत खतरा इसके डाटा सेंटरों के निर्माण का है। उल्लेखनीय है कि एआइ का सारा विकास दुनिया के चुनिंदा देशों में स्थित डाटा सेंटरों और सर्वरों पर केंद्रित है। अभी ज्यादातर डाटा सेंटर अमेरिका, रूस और चीन में हैं और अब भारत जैसे कुछ देशों में इनके निर्माण में तेजी आई है। इससे चीन-अमेरिका-रूस का एकाधिकार टूटने की स्थिति बनती है। डाटा सेंटर अत्यधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पर्यावरणवादी लोग दुनिया भर में डाटा सेंटर बनाने के खिलाफ हैं। अमेरिका में इंटरनेट मीडिया पर लोग समूह बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण इस क्षेत्र में खुद का वर्चस्व बनाए रखने की होड़ है। चीन और रूस जैसे देश इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करके गलत जानकारी फैला सकते हैं, ताकि अमेरिका में डाटा सेंटर का निर्माण रुक जाए। इससे चीन और रूस को फायदा होगा, क्योंकि वे खुद एआइ में आगे निकलना चाहते हैं। एआइ की मदद से फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाकर विरोध की आग भड़काई जा सकती है। गलत जानकारियां यदि विरोध को बढ़ाती हैं तो इससे एआइ का विकास धीमा पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एआइ में बढ़त रखने वाले देशों में तनाव पैदा होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ेगा। आज भी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देशों के बीच जो तनाव है, उसमें तकनीक और एआइ पर अपनी पकड़ कायम रखने की इच्छा की एक भूमिका अवश्य देखी जा सकती है।

एआइ तकनीक बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह, चेहरा पहचान और डीपफेक जैसी विधियों से प्राइवेसी और निजता में सेंध लगा रही है। यह व्यक्तिगत जानकारी को बिना सहमति के एकत्र कर प्रोफाइलिंग और निगरानी को संभव बनाती है। भारत में भी फेशियल रिकग्निशन और डाटा उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं। भारत के लिए, जो डाटा अर्थव्यवस्था के साथ तेज विकास कर रहा है, यह हाइब्रिड खतरे का संकेत है। शायद यही वजह है कि भारत सरकार इस मामले में अत्यधिक सतर्कता बरत रही है। उसने चीन में बने गैजेट्स को संदेह से देखना शुरू किया है और टिकटाक समेत अन्य दर्जनों चीनी एप्स को अपने यहां प्रतिबंधित किया है। इन उपायों से खतरा कम तो हुआ है, लेकिन टला नहीं है। वह इसलिए क्योंकि एआइ तकनीक इंटरनेट मीडिया, वेब ब्राउजिंग और बायोमीट्रिक डाटा से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करती है, जिससे विस्तृत प्रोफाइल बनते हैं। फेशियल रिकग्निशन और वायस रिकग्निशन जैसी तकनीकें बिना सहमति के निगरानी करती हैं, जो सेंट्रल डाटा बेस में संग्रहीत होती है। डीपफेक एआइ से फर्जी वीडियो/आडियो बनाकर निजता भंग होती है, जैसे बड़ी हस्तियों की छवियों (सेलिब्रिटी इमेज) का दुरुपयोग होता है।

देशों की सरकारों और बड़ी कंपनियों के लिए अपनी रणनीतिक और कारोबारी गोपनीयता को कायम रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमारे देश के कुछ उदाहरण इस मामले में प्रासंगिक हैं। जैसे, तेलंगाना पुलिस के फेशियल रिकग्निशन डेटा लीक मामले में व्यक्तिगत डाटा लीक हुआ, जिससे गोपनीयता का खतरा बढ़ा। चेन्नई और पंजाब पुलिस के फेसटैग और स्मार्ट पुलिसिंग साफ्टवेयर से संदिग्धों का डाटाबेस तैयार किया गया तो पता चला कि इस काम में निजता से जुड़ी पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। ध्यान रखना होगा कि ऐसे ही मामलों से जुड़ी सुनवाई में बांबे हाईकोर्ट ने एआइ-जनरेटेड इमेज को निजता का उल्लंघन माना, जबकि डीपफेक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। जाहिर है एआइ के कारण ये चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।

कैसे साधेंगे एआइ की चुनौतियां : तकनीक के मामले में एक बात सच साबित होती है कि इसके आगमन पर आगे बढ़ा जा सकता है, पीछे लौटना संभव नहीं होता। इसलिए आज अगर भारत में आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां एआइ और स्मार्टफोन पर बिना सहमति के चालू रहने वाले एप्स के जरिये खतरे में हैं या फिर रूस द्वारा गढ़े गए डीपफेक अमेरिका के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं तो इन चुनौतियों को साधने के लिए कुछ उपाय सख्ती से लागू करने की जरूरत बनती है। चूंकि खतरे स्थानीय से ज्यादा वैश्विक हैं, इसलिए इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सहमतियों-समझौतों की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय एआइ समझौता लागू कराया जा सकता है, जिसमें गोपनीयता कायम रखने और गलत सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर बंदिशें लगाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। एआइ तकनीकें और डाटा सेंटर जिस तरह से पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं, उनके मद्देनजर एआइ कंपनियों को निर्देशित किया जा सकता है कि वे नुकसान की समुचित भरपाई करने के साथ अपनी तकनीकों को पर्यावरण-हितैषी बनाने पर जोर दें। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर एआइ के इस्तेमाल से कामकाज का स्वरूप बदलता है तो लोगों को इसका विकल्प मिले कि वे खुद को एआइ के मुताबिक प्रशिक्षित करें, ताकि उनके रोजगार-नौकरियों पर नकारात्मक असर न पड़े।

Dainik Jagaran Page No-9

अपराध के पांव

निर्भया कांड की दिल दहला देने वाली घटना ने सामाजिक संवेदनाओं को पूरी तरह झकझोर दिया था। उसके बाद इस तरह के घिनौने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून को और सख्त किया गया, लेकिन जमीन पर उसका प्रभावी असर कम ही नजर आता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सोमवार की रात चलती कार में एक विवाहिता से सामूहिक बलात्कार की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वारदात में भी विकृत मानसिकता का बर्बर चेहरा सामने आया है। आरोपियों ने विरोध करने पर न सिर्फ पीड़ित महिला की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि बाद में उसे चलती कार से सड़क के किनारे फेंक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर सवाल है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सुरक्षा एजंसियां अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं कर रही हैं?

गौरतलब है कि फरीदाबाद में दो आरोपियों ने देर रात किसी वाहन का इंतजार कर रही एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने के बजाय गुरुग्राम की ओर ले गए तथा कार के अंदर ही उसके साथ मारपीट कर बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पीड़ित महिला को कई घंटे कार में घुमाते रहे और करीब तीन बजे राजा चौक के पास तेज रफ्तार कार से उसे बाहर धकेल दिया। हैरत की बात है कि आरोपी रातभर इस कार को सड़कों पर दौड़ाते रहे, लेकिन पुलिस के किसी गश्ती दल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी नाके पर उसे रोका गया। इससे पुलिस की सजगता और सतर्कता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। चलते वाहन में इस तरह की वारदात के कई मामले में सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस ने इनसे कोई सबक नहीं लिया है। वह घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है, लेकिन अपराध को रोकने का दायित्व बोध कोसों दूर रह जाता है।

Jansatta Page No-6

उम्मीदों की सुबह

मोनिका राज

दुनिया मेरे आगे

नूतन वर्ष को विश्वभर में नए आरंभ, अवसर और नवीकृत आशाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब लोग पिछले वर्ष पर चिंतन करते हैं। सफलताएं, गलतियां, चुनौतियां और जो जीवन की सीख मिली हैं और अपने आप को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। दरअसल, एक से दूसरे वर्ष में परिवर्तन केवल कैलेंडर की संख्या बदलने जैसा है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक महत्त्व बहुत गहरा होता है। यह लोगों को जीवन में एक प्रकार की समाप्ति का अनुभव कराता है और नए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर देता है। यही वजह है कि नूतन वर्ष आत्मनिरीक्षण, प्रेरणा और आत्म-सुधार का समय बन जाता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी इस अवसर को एक महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में उपयोग कर सकता है।

यह हमें आत्म निरीक्षण की ओर प्रेरित करता है, जो व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला और अहम कदम है। पिछले वर्ष को पीछे मुड़कर देखना यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या सफल रहा और क्या नहीं। यह समय होता है अपनी उपलब्धियों को पहचानने का, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों, और उन प्रयासों की सराहना करने का, जिनका परिणाम हमेशा उम्मीद के अनुसार नहीं आया। आत्म निरीक्षण में असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करना भी शामिल है, लेकिन इसके लिए आत्म-आलोचना की आवश्यकता नहीं है। अपने पिछले अनुभवों को समझना लोगों को मूल्यवान सबक सिखाता है, उन्हें मानसिक दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह सजग आत्म निरीक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और सतत जीवन की नींव रखता है, जो केवल दिनचर्या या संयोग से संचालित न होकर जानबूझ कर चुने गए रास्ते पर आधारित होता है।

जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और वर्ष के बदलने का समय यह याद दिलाता है कि बदलाव आवश्यक और विकास के लिए अहम है। यह व्यक्ति को अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने, सोच-समझकर जोखिम लेने और नए अवसरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें पहले भय या हिचकिचाहट के कारण टाला गया हो।

यह मौका एक खाली कैनवास की तरह है, जो हमें यह तय करने का अवसर देता है कि हम वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत विकास, करिअर, स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में केंद्रित कर सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में प्राथमिकताओं को पहचानना, बड़े लक्ष्यों को छोटे और साध्य हिस्सों में बांटना और बाधाओं को पार करने की रणनीति बनाना शामिल है। छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आत्म-विश्वास और प्रेरणा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हर छोटी सफलता व्यक्ति को संतोष और आत्मविश्वास देती है।

जीवन निरंतर विकास की यात्रा है और प्रत्येक वर्ष बेहतर आदतें अपनाने, हानिकारक व्यवहारों को छोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का अवसर प्रस्तुत करता है। चाहे वह नया कौशल सीखने के लिए समय समर्पित करना हो, शरीर की सेहत और क्षमता सुधारना, समय का बेहतर प्रबंधन करना या ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करना हो, नया वर्ष एक स्वाभाविक संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करे। छोटे और नियमित प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल सकते हैं, जिससे जीवन अधिक संतुलित, पूर्ण और सार्थक बनता है।

मानवीय संबंध भावनात्मक संतुलन और जीवन की खुशी के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। नए साल का जश्न परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ मनाने से अपनापन, कृतज्ञता और साझा खुशी की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा, यह समय पिछले मतभेदों को माफ करने, रंजिश को छोड़ने और संबंधों में सकारात्मकता और सहानुभूति के साथ फिर से शुरुआत करने का भी होता है। मजबूत रिश्ते न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं।

जीवन स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और वर्ष के बदलने का समय यह याद दिलाता है कि बदलाव आवश्यक और विकास के लिए अहम है। यह व्यक्ति को अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने, सोच-समझकर जोखिम लेने और नए अवसरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें पहले भय या हिचकिचाहट के कारण टाला गया हो। नए वर्ष को बदलाव को अपनाने के अवसर के रूप में देखने से व्यक्ति में अनुकूलन क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक दृढ़ता विकसित होती है, ये सभी आधुनिक जीवन की जटिलताओं में सफलतापूर्वक समाहित करने के लिए आवश्यक गुण हैं। साथ ही पिछले वर्ष की उपलब्धियों और अपने तथा दूसरों के प्रयासों की सराहना करने से व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। ध्यान, या दैनिक उद्देश्यों को निर्धारित करने जैसी सजगता की प्रथाएं लोगों को केंद्रित रहने, तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती हैं। कृतज्ञता और सजगता मिलकर आंतरिक शांति और संतोष की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति चुनौतियों का सामना आशावाद और शक्ति के साथ कर सकता है।

नया वर्ष एक प्रतीकात्मक अवसर है जो आत्मनिरीक्षण, लक्ष्य निर्धारण, आत्म-सुधार और संबंधों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। पिछले अनुभवों पर विचार करके, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करके, बदलाव को अपनाकर, सकारात्मक आदतों का विकास करके और कृतज्ञता को प्रोत्साहित करके व्यक्ति सुनिश्चित कर सकता है कि नूतन वर्ष केवल समय का परिवर्तन न रहकर जीवन को रूपांतरित करने वाला अवसर बन जाए।

मिलावटी पदार्थों से स्वास्थ्य पर संकट

खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल चुकी है। बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य वस्तुओं का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लगाई गई, तो इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं।

ज्ञान चंद पाटनी

देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल चुकी है। बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य वस्तुओं का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे सीधे तौर पर आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट का मामला इस चिंता को और बढ़ा देता है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 से 2024 तक बनाए गए 20 करोड़ लड्डुओं में नकली घी का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह देश के एक मशहूर ब्रांड के घी का नमूना भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और इसे सेहत के लिए घातक पाया गया। यह मामला वर्ष 2020 का है, लेकिन कार्रवाई अब हुई है। ऐसे मामलों में कार्रवाई में टालमटोल या देरी से भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मिलावट का गोरखधंधा करने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है।

मिलावट की समस्या केवल घी तक सीमित नहीं है। देश के बाजार नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में भी मिलावट होने के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। भुने हुए चने जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों में भी खतरनाक रंगों और रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। औरामाइन नामक रंग खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। यह कपड़ा और चमड़ा उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला रसायन है। इससे कैंसर और तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा होता है। इस तरह के खतरनाक रंगों का उपयोग खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद निरीक्षण में कई उत्पादों में इस तरह की मिलावट की पुष्टि हुई है। इससे साफ है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है, जिससे उपभोक्ता लगातार धोखा खा रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए देश भर में समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन मिलावट नहीं रुक पा रही। नकली मावा, नकली दूध और मिलावटी मसालों का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। मिठाई, बेसन, चटनी और यहां तक कि बच्चों के लिए बनाए गए उत्पादों में भी मिलावट की शिकायतें सामने आई हैं। मिलावट करने वाले खाद्य सामग्री में नकली और खतरनाक सामग्री का उपयोग कर आम उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दूध में डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और फार्मेलिन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए घातक हैं। इस तरह का दूध पीने से पेट संबंधी विकार, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। असंगठित क्षेत्र में मिलावट की समस्या ज्यादा है। ऐसे में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खाद्य गुणवत्ता की गारंटी आवश्यक है। मुश्किल यह है कि अब भी मिलावट करने वालों को पकड़ना और उन पर प्रभावी कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जब भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एजंसियां जांच करती हैं, बड़ी संख्या में नमूने विफल पाए जाते हैं, इसके बावजूद सख्त कदम नहीं उठाए जाते या कार्रवाई धीमी रहती है। इसका कारण भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और निगरानी तंत्र की कमजोरी है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कानून बनाना जरूरी है। साथ ही कानूनों का ठीक तरह से क्रियान्वयन भी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभागों को अपनी जांच और निरीक्षण प्रणाली को और मजबूत करना होगा, जिससे दोषियों को शीघ्रता से उचित दंड मिल सके। साथ ही उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना होगा, उन्हें मिलावटी उत्पादों की पहचान करने की समझ विकसित करनी होगी, ताकि वे इस तरह की घातक सामग्री से बच सकें। उन्हें ऐसे पदार्थों की बिक्री की शिकायत करने के लिए भी प्रेरित करना होगा, जिससे मिलावट करने वाले हतोत्साहित हो सकें। खाद्य उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों को अपनाना भी आवश्यक है। जैसे डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और स्रोत का पता चल सके। इसके अलावा किसानों और उत्पादकों को भी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

> खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित न होने से हमारा स्वास्थ्य तो खतरे में है ही, इससे देश के खाद्य उद्योग की विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मिलावट करने वालों पर प्रभावी रोक, उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण और सरकारी तंत्र की सक्रियता तीनों मोर्चों पर ध्यान देना होगा। सरकार, उद्योग जगत और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, ताकि खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज एवं निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत का निर्माण कर पाएंगे।

खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित न होने से हमारा स्वास्थ्य तो खतरे में है ही, इससे देश के खाद्य उद्योग की विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मिलावट करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई, उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण और सरकारी तंत्र की सक्रियता तीनों मोर्चों पर ध्यान देना होगा। सरकार, उद्योग जगत और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, ताकि खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत का निर्माण कर पाएंगे। वहीं, मिलावटी घी से जुड़े मामलों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सक्रियता पर भी सवाल खड़े किए हैं। जांच और कार्रवाई में देरी के साथ अनियमितता की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं का विश्वास डगमगाने लगा है। कई बार राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों के साथ तालमेल न होने से भी खाद्य सुरक्षा का कार्य बाधित होता है। राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी समस्या बढ़ाती है। कई मामलों में जांच अधूरी होती है या दस्तावेजों में गड़बड़ी के आधार पर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली उत्पादों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्राधिकरण को अपनी कार्यप्रणाली को निष्पक्ष और मजबूत बनाना होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना होगा, ताकि देश भर में सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें और जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया निश्चित रूप से तेज एवं निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। राज्य और केंद्र के खाद्य सुरक्षा विभागों तथा प्रयोगशालाओं को पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी एवं मानव संसाधन मुहैया कराने की जरूरत है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियमित और आकस्मिक निरीक्षण भी आवश्यक है। इस तरह की कार्रवाई से मिलावट करने वालों में भय पैदा होता है। उन्हें लगता है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसके परिणामस्वरूप वे ऐसे अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों से दूरी बना लेते हैं। मिलावट करने वालों को भी इस बात का भान होना चाहिए कि ऐसा करके वे अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

मिलावट के जरिए कोई दुकानदार भले ही ज्यादा मुनाफा कमा ले, लेकिन इस दुश्चक्र से वह और उसका परिवार भी नहीं बच सकता। असल में कोई भी व्यक्ति सभी तरह के खाद्य पदार्थ स्वयं पैदा नहीं कर सकता। उसे ज्यादातर वस्तुओं के लिए बाजार पर निर्भर रहना होता है। जब दूसरी चीजें भी मिलावटी आएंगी, तो वह खुद और उसका परिवार भी बीमारियों की चपेट में आएगा। इस तरह मिलावट के जरिए कमाया पैसा भी अस्पतालों के चक्कर काटने में ही खर्च होगा। बेहतर तो यह होगा कि हर व्यापारी मिलावट से दूर रहे और नैतिकता को अपने धंधे का मुख्य आधार बनाए। व्यापार तो लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन पैसे के लिए अपराध का रास्ता अपनाने का अंजाम भी खतरनाक ही होता है।

आर्थिक मोर्चे पर अच्छी संभावनाएं

जयंतीलाल भंडारी

2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दरों में कमी से तेज रफ्तार आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे

घरेलू मांग से आर्थिकी को मिलेगी गति। फाइल

नए साल 2026 की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार नव वर्ष भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाओं वाला होगा। केयर एज रेटिंग्स के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। ऐक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्ष में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंचती दिख सकती है। जहां भारत वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बन गया है। नए साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा। वैश्विक निवेश फर्म इन्वेसको का कहना है कि इस साल भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति कायम रखेगा। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चिताओं के बीच भारत को आर्थिक और वित्तीय सुधारों को गति भी देनी होगी।

नए वर्ष में घरेलू बाजार की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहल शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनेरगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल भी जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार होगा। बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, बुनियादी ढांचा, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण देश में जीएसटी और इनकम टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच जीएसटी संग्रह गत वर्ष की इसी अवधि से बढ़कर 14.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में बीते हुए वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और अधिक आयकर प्राप्ति का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिसंबर तक 8.44 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।

भारत द्वारा ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते इस साल अमल में आएंगे। साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी एफटीए आकार लेते हुए दिखाई देंगे। नए वर्ष में मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच हुए एफटीए के लाभ भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिलेंगे। इन सबके साथ-साथ नए वर्ष 2026 में कई और अच्छी आर्थिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वर्ष 2026 में भारतीय शेयर बाजार रफ्तार से आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ेगा। एक अप्रैल 2026 से नए श्रम कानून लागू होने से उद्योग-कारोबार व निर्यात बढ़ने का परिदृश्य उभरकर दिखाई देगा। निःसंदेह वर्ष 2026 में भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन भारत को अपनी मजबूत आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू खपत बढ़ाने, रोजगार सृजन और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के साथ आर्थिक सुधारों की डगर पर आगे बढ़ना होगा। इन सुधारों के तहत अगली पीढ़ी के सुधार, जीवन एवं कारोबारी सुगमता, बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशासन को सशक्त बनाने और आर्थिकी को मजबूती देने संबंधी सुधार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश को कृषि, बैंकिंग, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज आदि सुधारों को भी गति देना होगा।

आशा है कि सरकार नए साल में विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) समिति की उस रिपोर्ट को अवश्य ध्यान में रखेगी, जिसमें कहा गया है कि भारत को उद्योग-कारोबार के मजबूत विकास के लिए आर्थिक-वित्तीय क्षेत्र में तेज सुधारों के साथ निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देना होगा। नए साल में विनिर्माण गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना है। यह भी उम्मीद है कि आने वाले समय में डालर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और कर सुधार एवं ब्याज दर में कटौती से विकास दर को रफ्तार मिलेगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

भविष्य के भारत को बनाने का समय

गिरीश्वर मिश्र

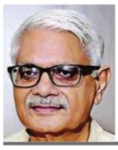

नए वर्ष में हमें संयत होकर इस पर भी गहनता के साथ विचार करना होगा कि विकसित भारत का स्वरूप कैसा होगा?

पिछले एक दशक में भारत की छवि निश्चित रूप से एक सशक्त देश के रूप में निखरी है। नए वर्ष में इस बदलते भारत के भविष्य के बारे में सोचते हुए हमें देश की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और आधुनिक राष्ट्र-राज्य की संकल्पना, दोनों को ध्यान में रखना होगा। लोक की स्मृति में अभी भी नैतिक और न्यायपूर्ण शासन के लिए रामराज्य की अमिट छवि कायम है। इसलिए जहां वैश्वीकरण के अनुकूल आकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा, वहीं नैतिकता, सत्य तथा अहिंसा जैसे मानदंडों की भी चिंता करनी है। देश की प्रगति की कथा को देखें तो उसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मिलते हैं। इस नए वर्ष में हमें संयत होकर यह विचार करना होगा कि विकसित भारत कैसा होगा, क्योंकि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बहुलताएं हैं, जिसे लेकर कुछ विचारक देश की मौलिक एकता को प्रश्नांकित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतीय दृष्टि में बहुलता अंतर्निहित मौलिक एकता का ही प्रकटन होती है-एकम् सद् विप्रा बहुधा वदंति। इसी एकता को खोजना पहचानने का उद्देश्य होना चाहिए। पूरे प्राणी जगत में निकटता को आधार बना कर विविधताओं का सह-अस्तित्व और पारस्परिक संवाद इस भारत का मौलिक सोच रहा है। यह अकारण नहीं है कि परिवार या कुटुंब का रूपक हमारे सोच में केंद्रीय है। देश की एकता, देश को अपनाने के भाव और देशप्रेम के लिए भी यह दृष्टि जरूरी है।

बीता वर्ष भारत के लिए चुनौतियों भरा रहा। अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात, रुपये की हैसियत, निवेश तथा भुगतान संतुलन आदि को लेकर मुश्किलें खड़ी कर दीं। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी हितों को आक्रामक ढंग से आगे धकेलने की नीति ने हमारा अहित किया। इसे देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए भारत ने कई कदम उठाए गए। जीएसटी की दरें कम की गईं और श्रम कानूनों में बदलाव लाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है कि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितिता की विकट परिस्थितियों में भी भारत की जीडीपी की दर विश्व में अव्वल दर्जे की बनी रही। खुदरा महंगाई दर भी आठ साल में सबसे कम रही। अच्छी पैदावार, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कच्चे तेल की कम कीमतों ने इन परिस्थितियों में मदद की। शेयर बाजार में घरेलू निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बने। आयकर रिटर्न के दाखिलों और कर-संग्रह में भी सुधार हुआ। बिजली, शहरी विकास, खनन, और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में नई पहलें की गईं। भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और अनुमान है कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर जीडीपी के साथ वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अवधेश राजपूत

सामाजिक संरचना की दृष्टि से देश में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है, जिससे खपत और शहरीकरण में वृद्धि और गरीबी में कमी के आसार बन रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचा विस्तृत हो रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआइ), अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रो और बुलेट ट्रेन आदि को लेकर भी प्रगति दर्ज हो रही है। मेड इन इंडिया के तहत मैन्यूफैक्चरिंग, आइटी, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप्स में भारी वृद्धि से रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र में प्रगति की संभावना दिख रही है और स्वदेशी विकास की नीति अपनाई जा रही है। अनुमान है कि 5-जी और रोबोटिक्स के उपयोग का दायरा विस्तृत होता जाएगा। अब आनलाइन खरीदारी और ओटीटी प्लेटफार्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भविष्य में एआइ का प्रभुत्व और भी बढ़ेगा। उसी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण सरोकार बन रहा है। यह भी याद रखना जरूरी है कि देश का भविष्य सिर्फ आर्थिक उन्नति के सूचकों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास को केवल वृद्धि दर के अर्थ में ही नहीं, बल्कि रोजगार के अधिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता और आम जनों के जीवन-स्तर में उन्नति के संदर्भ में भी देखना होगा। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिकी को ज्ञान-केंद्रित और सामाजिक रूप से ज्यादा उत्तरदायी भी बनाना होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए अवसर है, पर हम अपनी सीमाओं को भी अनदेखा नहीं कर सकते। युवा भारत को एक पूंजी के रूप में घोषित किया जाता है, पर इसके लिए कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होगा। कौशल विकास की कमी और युवाओं में बेरोजगारी के चलते समाज में असंतोष पैदा हो रहा है। शिक्षा की पहुंच, उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता को लेकर संशय बना हुआ है।

इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। अभी भी महिला श्रम-भागीदारी निम्न दर पर है। आय और संपत्ति की असमानता भी बढ़ी है और अनौपचारिक क्षेत्र की असुरक्षा बनी हुई है। साथ ही जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय विषमताएं भी हैं। इन्हें दूर कर बहिष्कृत जनों का समावेश जरूरी होगा, अन्यथा राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक ध्रुवीकरण कर चुनावी लाभ लेने का चक्र चलता रहेगा।

नए वर्ष में यह अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीमाओं पर आतंकी तत्वों की ओर से लगातार चुनौती आती रहती है। ऐसे में सतत चौकसी और सावधानी की जरूरत बनी हुई है। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं से मिलते संकेत जलवायु-परिवर्तन और तापमान में लगातार वृद्धि जैसे बदलाव पर्यावरणीय संकट की जटिलता को बता रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य दृष्टि प्रकृति के साथ संतुलन और सह-जीवन पर बल देती आई है। हमें अनिवार्य रूप से उपभोक्तावाद पर लगाम लगाते हुए ऐसी जीवनशैली अपनानी होगी, जो पर्यावरण और सतत विकास के विरुद्ध न हो। भारत का भविष्य उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा है, लेकिन उसे गरीबी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यह भी जरूरी होगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बढ़े और सामाजिक संवाद तथा सहिष्णुता को बढ़ावा मिले।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे का हो रहा है विस्तार

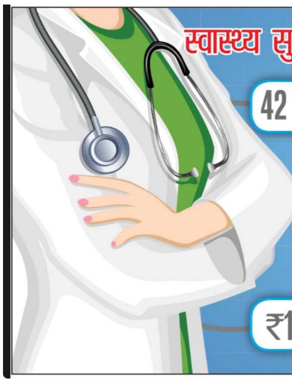

42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं अक्टूबर, 2025 तक

86 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया है स्कीम से

1 करोड़ गिग वर्कर्स को भी कवर किया गया है स्कीम में

₹1.52 लाख करोड़ खर्च बचा है परिवारों का आयुष्मान भारत स्कीम से अब तक

केंद्र सरकार देशवासियों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे का विस्तार कर रही है। आयुष्मान योजना एक बड़े वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। इस योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कवरेज मुहैया कराया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी इस योजना से जोड़ गया है। देश में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नई मेडिकल सीटें जोड़ी जा रही हैं। 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और खर्च बढ़ने से गुणवत्तपूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक नागरिकों की पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।

केंद्र व राज्य सरकारों का स्वास्थ्य व्यय जीडीपी के मुकाबले

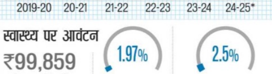

*लक्ष्य रखा है सरकार ने

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

स्वास्थ्य पर आवंटन

₹99,859 करोड़ आवंटित किए गए बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए

1.97% जीडीपी का स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया बजट आवंटन

2.5% आवंटन जीडीपी का करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने

200 नए डेकेयर कैंसर सेंटर बनाने की घोषणा, स्थानीय स्तर पर इलाज और कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा

मेडिकल शिक्षा का विस्तार

10,023 नई मेडिकल सीटें मंजूर की भारत सरकार ने 2025 में

75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य है अगले 5 वर्ष में

₹15,023 करोड़ का खर्च आएगा नई मेडिकल सीटों पर

808 हो गई हैं मेडिकल कालेज की संख्या 2025 में

भारत में कुल कितने अस्पताल हैं

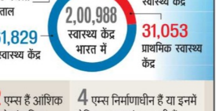

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

एम्स की संख्या

23 एम्स हैं भारत में वर्तमान में

7 एम्स पूरी तरह से संचालित

12 एम्स हैं आंशिक रूप से संचालित

4 एम्स निर्माणाधीन हैं या इनमें मेडिकल कक्षाएं चल रही हैं

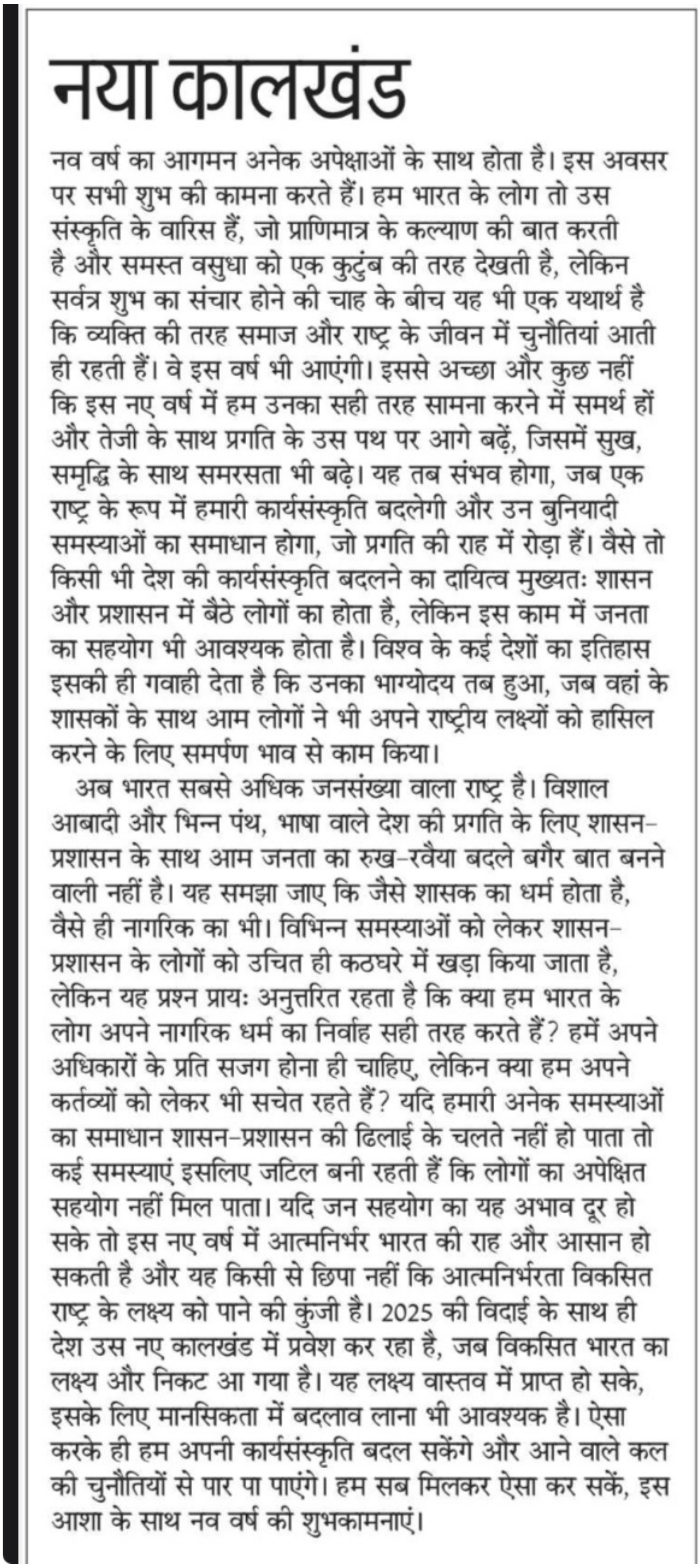

नया कालखंड

नव वर्ष का आगमन अनेक अपेक्षाओं के साथ होता है। इस अवसर पर सभी शुभ की कामना करते हैं। हम भारत के लोग तो उस संस्कृति के वारिस हैं, जो प्राणिमात्र के कल्याण की बात करती है और समस्त वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखती है, लेकिन सर्वत्र शुभ का संचार होने की चाह के बीच यह भी एक यथार्थ है कि व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र के जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं। वे इस वर्ष भी आएंगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में हम उनका सही तरह सामना करने में समर्थ हों और तेजी के साथ प्रगति के उस पथ पर आगे बढ़ें, जिसमें सुख, समृद्धि के साथ समरसता भी बढ़े। यह तब संभव होगा, जब एक राष्ट्र के रूप में हमारी कार्यसंस्कृति बदलेगी और उन बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा, जो प्रगति की राह में रोड़ा हैं। वैसे तो किसी भी देश की कार्यसंस्कृति बदलने का दायित्व मुख्यतः शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का होता है, लेकिन इस काम में जनता का सहयोग भी आवश्यक होता है। विश्व के कई देशों का इतिहास इसकी ही गवाही देता है कि उनका भाग्योदय तब हुआ, जब वहां के शासकों के साथ आम लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण भाव से काम किया।

अब भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विशाल आबादी और भिन्न पंथ, भाषा वाले देश की प्रगति के लिए शासन-प्रशासन के साथ आम जनता का रुख-रवैया बदले बगैर बात बनने वाली नहीं है। यह समझा जाए कि जैसे शासक का धर्म होता है, वैसे ही नागरिक का भी। विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन के लोगों को उचित ही कठघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन यह प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहता है कि क्या हम भारत के लोग अपने नागरिक धर्म का निर्वाह सही तरह करते हैं? हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना ही चाहिए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर भी सचेत रहते हैं? यदि हमारी अनेक समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की ढिलाई के चलते नहीं हो पाता तो कई समस्याएं इसलिए जटिल बनी रहती हैं कि लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। यदि जन सहयोग का यह अभाव दूर हो सके तो इस नए वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की राह और आसान हो सकती है और यह किसी से छिपा नहीं कि आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की कुंजी है। 2025 की विदाई के साथ ही देश उस नए कालखंड में प्रवेश कर रहा है, जब विकसित भारत का लक्ष्य और निकट आ गया है। यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। ऐसा करके ही हम अपनी कार्यसंस्कृति बदल सकेंगे और आने वाले कल की चुनौतियों से पार पा पाएंगे। हम सब मिलकर ऐसा कर सकें, इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं।

Dainik Jagaran Page No-8

'प्रगति' के बाद लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पूरी हुईं : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने 'प्रगति' मंच की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की

- सुधारों की गति बनाए रखने के लिए 'प्रगति' को आवश्यक बताया
- परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी उपयोग पर दिया बल

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 'प्रगति' की 50वीं बैठक में सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के मंत्र पर जोर दिया। कहा कि 'प्रगति' मंच का उपयोग करके राष्ट्रीय हित में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इनमें असम का बोगीबील रेल-सड़क पुल, जम्मू से बारामूला रेल परियोजना, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और गदरवाड़ा तथा लारा ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां निरंतर निगरानी और केंद्र-राज्य सहयोग का परिणाम हैं। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आने वाले वर्षों में 'सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन' (प्रगति) मंच को और मजबूत किया जाना चाहिए। सुधारों की गति बनाए रखने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 'प्रगति' आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को प्रगति मंच की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। एएनआइ

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया। मोदी ने कहा कि परिवर्तन का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि नागरिक समय पर सेवाओं, शिकायतों के त्वरित समाधान और जीवन स्तर में सुधार के बारे में वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक आधारित मंच शासन व्यवस्था में आए बड़े बदलाव का प्रतीक है। इससे केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बना है। समय पर निर्णय, मजबूत समन्वय और तय जिम्मेदारी से सरकारी कामकाज की गति तेज होती है और उसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है।

पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा : एएनआइ के अनुसार, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं पांच राज्यों में चल रही हैं और इन पर 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं की निगरानी केवल कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीन पर उनके प्रभाव को भी देखा जाना चाहिए। पीएम ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में प्रगति मंच के माध्यम से 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। वर्ष 2014 से अब तक 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

पीएम श्री विद्यालय योजना पर की बात

प्रधानमंत्री ने पीएम श्री विद्यालय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना को केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने इसे भविष्य की शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसका क्रियान्वयन परिणाम आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे योजना की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि पीएम श्री विद्यालय अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए आदर्श बनें। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से विद्यालयों का स्वयं दौरा करने का भी आग्रह किया।

Dainik Jagaran Page No-3

EDU
TERIA